क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 02 अंक: 83, बुधवार, 17 अप्रैल, 2019, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

छठे चरण के लिए अधिसूचना जारी, सात राज्यों की 59 सीटों पर 12 मई को होगा मतदान

नेशनल डेस्क । चुनाव आयोग ने मंगलवार को लोकसभा के छठवें चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत 12 मई को सात राज्यों की 59 सीटों पर मतदान होगा। सात चरणों में हो रहे लोकसभा चुनाव की शुरूआत 11 अप्रैल से हो चुकी है और 19 मई को आखिरी चरण में संपन्न होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में सात चरणों में चुनाव होगा। दिल्ली की सात सीटों के लिए मतदान छठवें चरण में होगा। वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच ट्विटर पर हुई बहस के बीच सूत्रों ने दावा किया कि दलों के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है और बुधवार को एक बार फिर दोनों दल सीट बंटवारे पर बातचीत के लिए बैठक कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी दिल्ली की सात में से चार लोकसभा सीटें आप को देने को तैयार है ताकि उनका गठजोड़ भाजपा को हरा सके। भाजपा ने2014 में दिल्ली की सातों सीटों पर जीत का परचम लहराया था। छठे चरण में 12 मई को जिन सीटों पर मतदान होगा, उनमें कुछ महत्वपूर्ण सीटें बिहार की पूर्वी तथा पश्चिम चंपारण, वैशाली, गोपालगंज, सीवान और महाराजगंज सीटें हैं। छठवें चरण में उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, डुमरियागंज, संतकबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और भदोही में मतदान होगा। वहीं, दिल्ली की तरह हरियाणा में भी एक ही चरण मतदान होगा। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़, दमोह, खुजराहो, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद सीटों पर भी 12 मई को मतदान होगा।

दिल्ली से अभी तक भाजपा प्रत्याशियों की नहीं हुई घोषणा

नई दिल्ली। दिल्ली में मंगलवार से लोकसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है लेकिन भाजपा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक सात लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है जिससे पार्टी कार्यकर्ता निराश हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विलंब होने से प्रचार में कठिनाई होगी। बहरहाल, भाजपा के उपाध्यक्ष और दिल्ली इकाई के प्रभारी श्याम जाजू ने कहा कि उम्मीदवारों की घोषणा में ''विलंब नहीं'' हो रहा है और हर चीज योजना के मुताबिक चल रही है। जाजू ने कहा, ''हम सही समय पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करेंगे।'' नामांकन प्रक्रिया 23 अप्रैल को खत्म होगी। जाजू ने इन बातों को भी खारिज कर दिया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच संभावित गठबंधन को लेकर भी भाजपा उम्मीदवारों की घोषणा में विलंब हो रहा है। जाजू ने कहा, ''हम संगठन वाली पार्टी हैं। पार्टी के नेता निर्णय करते हैं और हम एक व्यवस्था में चलते हैं। भाजपा दूसरे दलों से अलग है जहां एक व्यक्ति निर्णय करता है।'' बहरहाल, स्थानीय पार्टी नेताओं का कहना है कि विलंब से स्थानीय नेताओं को अपने प्रचार की तैयारी में कठिनाई होगी क्योंकि 12 मई को होने वाले चुनावों के लिए बचे-खुचे दिन हैं। भाजपा के एक अन्य नेता ने दावा किया कि कांग्रेस-आप गठबंधन पर पार्टी ''अंतिम निर्णय'' का ''इंतजार'' कर रही है जिसके बाद उम्मीदवारों की घोषणा होगी।

मोदी के बोल

मलाई खाने वालों को देश की कैसी चिंता, किसान विरोधी है ओडिशा सरकार: मोदी

नेशनल डेस्क (एजेंसी) ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे देश में सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। कमी रही है तो उस पैसे के सही इस्तेमाल की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे भेजे जा रहे हैं, वो आप तक पूरे पहुंचें या नहीं। ओडिशा के संबलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पहले चरण की वोटिंग के बाद ओडिशा से जो संकेत आए हैं उससे साफ है कि दिल्ली में फिर एक बार मोदी सरकार और ओडिशा में भाजपा सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि चौकीदार को समर्थन देने के लिए धन्यवाद।

मोदी की रैली

- 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तो ओडिशा के किसान परिवारों के बैंक खातों में सीधी मदद की व्यवस्था हम करने वाले हैं। कोई भी दलाल आपके पैसे पर पंजा नहीं मार पाएगा।
- पहले की भ्रष्ट और कमजोर सरकारों का ही परिणाम है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी संपन्न ओडिशा की जनता गरीब ही रही।
- जब इस चौकीदार ने विपक्षियों के भ्रष्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया तो इनको इतना कष्ट हुआ है कि ये मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। भाजपा की नई सरकार बनने पर एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। इसके तहत देशभर की नदियों के, समुद्र के, बारिश के पानी को जरुरतमंदों तक पहुंचाने का मिशन चलाया जाएगा। इससे पानी से जुड़ी समस्याएं कम हो पाएंगी।
- जमीन के नीचे की सम्पदा और यहां के जंगलों की समृद्धि ओडिशा की शक्ति है। ओडिशा की यही शक्ति भारत को ताकत दे रही है लेकिन इन जंगलों में रहने वालों की पूछ नहीं बल्कि लूट हुई है।
- जिनकी प्राथमिकता सिर्फ मलाई खाने की रही हो, उनको आपकी चिंता कैसे होगी? चिटफंड और खनन माफिया को ही अगर सरकारें संरक्षण देती रहेंगी, तो सामान्य मानवी की चिंता कैसे संभव है। कोल ब्लाक घोटाले पर कैसे उंगली उठी है ये भी लोग जानते हैं।

कांग्रेस की आप को दो टूक- राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया, अब केजरीवाल बंद करें लुकाछिपी

नई दिल्ली (एजेंसी) ।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) के साथ गठबंधन को लेकर बनी असमंजस की स्थिति के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और अब अरविंद केजरीवाल को लुकाछिपी बंद करनी चाहिए। गठबंधन के सवाल पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि राहुल जी ने ट्वीट करके सबकुछ स्पष्ट कर दिया है। अगर आप कांग्रेस को राष्ट्रीय विकल्प मानते हैं तो क्या हर जगह हम समर्पण करें? अरविंद केजरीवाल जो लुकाछिपी का खेल खेल रहे थे...मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी लुकाछिपी बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल यूटर्न मत लीजिए क्योंकि आप इसके लिए जाने जाते हैं। आपके बारे में लोग बताते हैं कि आप किसी की बी टीम हैं। खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाते हुए चीजों को स्पष्ट कर दिया है। अब गेंद केजरीवाल के पाले में है। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन का मतलब भाजपा का सूपड़ा साफ होना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस आप को चार सीटें देने की इच्छुक है। परन्तु केजरीवाल जी ने एक और यूटर्न ले लिया है। गांधी ने कहा कि हमारे दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, लेकिन समय बीता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष के ट्वीट के जवाब में केजरीवाल ने कहा, ''कौन-सा यूटर्न ? अभी तो बातचीत चल रही थी। आपका ट्वीट दिखाता है कि गठबंधन आपकी इच्छा नहीं बल्कि, मात्र दिखावा है। मुझे दुःख है कि आप बयानबाकी कर रहे हैं। आज देश को मोदी-शाह के खतरे से बचाना अहम है। दुर्भाग्य है कि आप उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में भी मोदी विरोधी वोट बाँट कर मोदी जी की मदद कर रहे हैं।'' दरअसल, कांग्रेस सिर्फ दिल्ली में गठबंधन चाहती है तो आप दिल्ली के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ में भी तालमेल पर जोर दे रही है।

तेलंगाना के 2 कांसैप्ट,एक पर मोदी, दूसरे पर काम कर रहे राहुल गांधी

इलैक्शन डैस्क । भाजपा ने पी.एम. किसान सम्मान निधि (सालाना 6,000 रुपए) का लाभ अब हर किसान को देने का वायदा अपने संकल्प पत्र में किया है और इसके तहत मोदी सरकार ने 2,000 रुपए की पहली किस्त चिन्हित किए गए काफी किसानों के खातों में जमा भी करवा दी है। यह देश में कोई नई योजना नहीं है। इस तरह की योजना तेलंगाना में टी.आर.एस. सरकार राज्य में पहले ही लागू कर चुकी है। फर्क सिर्फ इतना है कि राज्य सरकार किसानों को चैक के जरिए सालाना 6 की जगह 4,000 रुपए की राशि एकमुश्त मुहैया करवा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अलग से किसान बजट लाने का वायदा किया है। इस तरह का आइडिया भी तेलंगाना सरकार का ही था। सरकार ने 2017 में अलग से किसान बजट लाने का ऐलान भी कर दिया था। इसके लिए 50 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भी कर दिया गया था लेकिन संविधान में प्रावधान नहीं होने के कारण यह संभव नहीं हो सका। पी.एम. किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को 6,000 रुपए की राशि सालाना दी जाती रहेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने इसी तरह की रायतु बंधु बंधु किसान योजना की 10 मई 2018 को करीमनगर जिले से शुरूआत की थी। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में 12,000 करोड़ रुपए किसानों को आबंटित किए थे। किसानों को खरीफ और रबी फसल के अनुसार यह आर्थिक सहायता 2 चरणों में दी जाती है। किसानों को चैक के जरिए प्रति एकड़ 4,000 रुपए दिए जाते हैं। यह राशि 8 हजार रुपए सालाना हो सकती है। मोदी सरकार और तेलंगाना सरकार की योजना में यह बड़ा अंतर है। किसानों को दी जाने वाली राशि में भी काफी फर्क है। के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में तेलंगाना राष्ट्र समिति (टी.आर.एस.) ने राज्य विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान चायतु बंधु योजना को अपनी एक बड़ी सफलता के तौर पर पेश किया था। इस योजना की शुरूआत के 6 महीने बाद ही तेलंगाना में चुनाव हुए थे और चंद्रशेखर राव की पार्टी टी.आर.एस. ने इनमें जीत दर्ज की थी।

मोदी बोले- किसान मरे तो मुद्दा, जवान शहीद हो तो वह चुनावी मुद्दा क्यों नहीं

नई दिल्ली। चुनावी जीत के लिए अपने भाषणों में सेना के नाम का उपयोग करने के आरोपों को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रवाद और सैनिकों का बलिदान भी उतने ही महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दे हैं जितना किसानों की मौत। दूरदर्शन को दिए एक साक्षात्कार में मोदी ने कहा कि देश पिछले 40 साल से आतंकवाद से जूझ रहा है। कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना न्याय पर टिप्पणी करते हुए मोदी ने कहा कि इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस ने यह मान लिया है कि पिछले 60 साल में उसने देश के लोगों के साथ 'महान अन्याय' किया है। उन्होंने कहा, ''यदि हम लोगों को नहीं बताएंगे कि इस पर (आतंकवाद पर) हमारे विचार क्या हैं तो फिर इसमें क्या तर्क रह जाएगा। क्या कोई देश बिना राष्ट्रवाद की भावना के आगे बढ़ सकता है?'' एक ऐसे देश में जहां हजारों की संख्या में इसके सैनिकों ने बलिदान दिया हो, क्या यह चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए? जब किसान की मौत होती है तो वह चुनावी मुद्दा बन जाता है लेकिन जब एक सैनिक शहीद होता है तो वह चुनावी मुद्दा नहीं बन सकता? यह कैसे हो सकता है?'' बता दें कि पिछले हफ्त बता दें कि पिछले हफ्ते मोदी ने एक चुनावी सभा में पहली बार मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं से प्रश्न किया था कि क्या वह अपना पहला मत पाकिस्तान के बालाकोट में किए गए हवाई हमले को समर्पित कर सकते हैं।साथ ही उन्होंने साथ ही उन्होंने लोगों से उनका वोट पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को समर्पित करने का भी अनुरोध किया था। उनके इस बयान पर विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चुनाव में जीत के लिए सुरक्षा बलों के नाम का उपयोग कर रहे हैं।

हम भाजपा को 370 कभी रद्द नहीं करने देंगे : आजाद

श्रीनगर (एजेंसी) ।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने मंगलवार को कहा कि यदि भाजपा अगले 200 सालों तक शासन करेगी, कांग्रेस उनको कभी भी अनुच्छेद 370 को रद्द करने की इजाजत नहीं देगी। उन्होंने कहा कि जब तक भारत में कांग्रेस मौजूद है, तब तक हम भाजपा को धारा 370 को रद्द करने की इजाजत नहीं देंगे। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिला में पार्टी रैली को संबोधित करने के बाद आजाद ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से जीत हासिल करेगी। यहां जीत के बाद जी.ए. मीर और मैं रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर बरसते हुए आजाद ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करती है लेकिन हर दूसरे दिन देश में एक बलात्कार की घटना होती है। भाजपा देश भर में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को दावा किया कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजग सरकार का रिकॉर्ड बहुत खराब है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर आरोप लगाया कि वह इन दोनों विषयों पर कांग्रेस के रूख को लेकर 'देश को गुमराह' करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सेना और सुरक्षा बलों के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सबसे ज्यादा, रिकॉर्ड संख्या में हमले मोदी सरकार के दौरान हुए हैं और इस दौरान आतंकवाद और घुसपैठ अपने चरम पर रहा है।

प. बंगाल में तीन सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार थमा

कोलकाता (एजेंसी) ।

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार को होने वाले मतदान के लिए पश्चिम बंगाल में तीन संसदीय क्षेत्रों में मंगलवार शाम पांच बजे चुनाव प्रचार थम गया। उत्तर बंगाल के तीन जिलों में स्थित जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और रायगंज लोकसभा सीटों के लिए दूसरे चरण में 18 अप्रैल को मतदान होगा। राज्य में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी), कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किये हैं। इन सीटों पर टीएमसी और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। तीनों सीटों पर करीब 41 लाख 24 हजार से अधिक मतदाता तीनों सीटों पर 42 मतदाताओं के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 2519191 है जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 2405050 है। इनमें 100 से अधिक किन्नर मतदाता भी हैं। मतदान के लिए पांच हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाये गये हैं। जलपाईगुड़ी (सु) में मौजूदा सांसद टीएमसी के विजय चंद्र वर्मन समेत 12 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में मतदाताओं की कुल संख्या 1721829 है जिनमें 884565 पुरूष और 845245 महिला हैं। मतदान के लिए इस संसदीय क्षेत्र में 1868 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। दार्जिलिंग सीट पर पिछले दो चुनावों से भाजपा का कब्जा रहा है। दोनों चुनावों में भाजपा को गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरूंग के समर्थन का भी बहुत बड़ा सहारा मिला। जीजेएम हालांकि एक बड़े आंदोलन के बाद दो खेमों में विभक्त हो चुका है तथा स्थानीय स्तर पर उसकी राजनीति भी बदल चुकी है। यहां से सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों समेत 16 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में कुल 1598863 मतदाता हैं जिनमें 806298 पुरूष और 712543 महिला हैं। इस क्षेत्र में कुल 1899 मतदान केंद्र बनाये गये हैं। रायगंज लोकसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 1595668 जिनमें से 828333 पुरूष तथा 767262महिला हैं।

मिशन 2019- भाजपा की चुनौतियां तीन गुना

इलैक्शन डैस्क (एजेंसी) ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान में कहा है कि इस बार 2014 के मुकाबले मोदी लहर अधिक है मगर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि भाजपा के सामने 2019 के चुनाव में तीन गुना अधिक चुनौतियां हैं। भाजपा की 2019 की सीटों की तालिका इस बात पर निर्भर करेगी कि 353 लोकसभा सीटों पर क्या होगा। 2014 में इन सीटों में से 74 प्रतिशत सीटें एन.डी.ए. को मिली थीं। भाजपा की इन सीटों पर राजनीतिक चुनौतियों को 3 श्रेणियों में डाला जा सकता है। भाजपा 2019 में कितनी सीटों पर जीतेगी? चुनाव संबंधी भविष्यवाणियां हमेशा खरतरनाक साबित होती हैं और उससे भी ज्यादा फर्स्ट पास्ट-द पोस्ट (एफ.पी.टी.पी.) सिस्टम में किसी भी पार्टी की सीटों की अंतिम तालिका दो पहलुओं का परिणाम होती है। पहला वोटों की हिस्सेदारी में बदलाव और दूसरा विपक्षी मतों की मजबूती। भारत की राजनीतिक भौगोलिक स्थिति की विभिन्नता का भी अर्थ है कि ऐसा पहलू राज्य स्तर पर भी महत्वपूर्ण होता है। एक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भाजपा की 2019 की तालिका 13 राज्यों की 353 सीटों पर होने वाले मतदान पर निर्भर करेगी। 2014 में इन सीटों में से 74 प्रतिशत सीटों पर भाजपा को विजय हासिल हुई थी। इन सीटों पर भाजपा की राजनीतिक चुनौतियों की 3 बड़ी श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में 8 राज्य हैं। यहां भाजपा और कांग्रेस व सहयोगी दलों के बीच सीधा मुकाबला है। ये राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात महाराष्ट्र और झारखंड हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में इन राज्यों की 162 सीटों में से भाजपा ने 151 सीटों पर जीत हासिल की थी। वर्तमान में भाजपा के सामने इन सीटों पर बड़ी चुनौतियां ये हैं कि वह इस बात को यकीनी बनाए कि 2014 के उसके मतदाता कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों को न अपनाएं। महाराष्ट्र को छोड़कर भाजपा ने 2014 के चुनाव में इन राज्यों में अपने दम पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में गठबंधन किया था। 2014 में इन राज्यों में एन.डी.ए. की यू.पी.ए. के मुकाबले वोटों की हिस्सेदारी काफी अधिक थी। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या 2014 के एन.डी.ए. के मतदाताओं का बड़ा हिस्सा यू.पी.ए. की ओर खिसक जाएगा? 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद इन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के परिणामों से इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। मतदाता राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में अलग-अलग राय रखते हैं। 8 राज्यों में से महाराष्ट्र और झारखंड को छोड़कर 2014 के गठबंधन विधानसभा चुनावों में बरकरार नहीं रहे। इन दोनों राज्यों में भाजपा एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और लोकसभा चुनावों के बाद कुछ राज्यों में अपनी सरकारें भी बनाईं। इन 6 राज्यों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि एन.डी.ए. की सीटों और मतों की हिस्सेदारी में 2014 के मुकाबले काफी गिरावट आई है। 2014 में 100 लोकसभा सीटों में भाजपा 96 पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। 2014 के बाद भाजपा की अंतिम तालिका गिरकर 58 रह गई है। इसी तरह 2014 के मुकाबले भाजपा की मतों की हिस्सेदारी भी गिरी है।

संपादकीय

गरीबी का जीव विज्ञान

नेताओं की बिगड़ी जुबान अब कोई नई खबर नहीं है। हर रोज देश के अलग-अलग हिस्सों से ऐसे समाचार आते हैं कि फलां नेता ने आपत्तिजनक बात कही, फलां नेता ने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और फलां ने तो फूहड़ता की सारी हदें ही पार कर दीं। तकरीबन हर दल में ऐसे नेता हैं, जिन्होंने चुनाव आयोग की आचार संहिता को मुंह चिढ़ाने की जैसे ठान ही ली है। यहां महाराष्ट्र के एक नेता का बयान गौर करने लायक है। एक चुनावी सभा में उन्होंने यह स्वीकार किया कि चुनाव के दौरान आचार संहिता को मानने का दबाव रहता है, लेकिन 'भाड़ में गया कानून, आचार संहिता को भी हम देख लेंगे, जो बात हमारे मन में है, वह बात अगर मन से नहीं निकले, तो घुटन-सी महसूस होती है।' चुनाव वह समय है, जब हम यह जान पाते हैं कि जिनको हम अपना प्रतिनिधि बनाते हैं, उनके मन में कितने घटिया स्तर की बातें होती हैं। सोमवार को एक साथ ऐसी कई खबरें आईं, जिनमें नेताओं के मन की ऐसी सोच का निचला स्तर सामने आ गया। रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा की जयाप्रदा पर जो टिप्पणी की, उसे अश्लील के अलावा कुछ और करार नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ हिमाचल के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने मंच से बाकायदा गाली ही दे दी। इसी के साथ यह भी खबर आई कि 'चौकीदार चोर है' के नारे पर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। नेताओं के इस तरह के बिगड़े बोल पूरी तरह से कोई नई चीज है, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले एक दौर में जिस तरह राजनीति और सार्वजनिक जीवन का चारित्रिक पतन बढ़ा है, उससे इस तरह की चीजों में वृद्धि तो हुई ही है। एक और फर्क यह पड़ा है कि मोबाइल कैमरे और सोशल मीडिया के कारण अब हर कोई निगरानी में रहता है। हर सार्वजनिक सभा, हर बैठक, हर बातचीत कहीं न कहीं रिकॉर्ड हो रही होती है। अब कोई भी, कुछ भी कहकर आसानी से बच नहीं पाता। कुछ ही समय में पूरा देश जान जाता है कि उसके नेताओं के मुंह से कौन से फूल झर रहे हैं। साइबर युग में नेताओं को जिस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए थीं, उन्होंने कभी नहीं बरती और अक्सर ऐसा लगता है कि उन्हें शायद इसकी परवाह भी नहीं है। यह किसी एक दल, किसी एक नेता या किसी एक प्रदेश में नहीं हो रहा, बल्कि यह शायद पूरे देश की राजनीति का चरित्र ही बन गया है। बात सिर्फ नेताओं और राजनीति के चारित्रिक दोष की नहीं है, समस्या शायद ज्यादा गहरी है। हम राजनीति के उस दौर में पहुंच चुके हैं,जहां चुनावी वादे, घोषणापत्र, नीतियां और यहां तक कि वैचारिक जुड़ाव महज औपचारिकता भर रह गए हैं। कम से कम वोट मांगने वालों का इन पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं रहा। उन्हें नहीं लगता कि उनके वादे और उनकी प्रतिबद्धताएं लोगों में इतना भरोसा जगा पाएंगी कि वे इसी के चलते उन्हें वोट देंगे। इसलिए वोट पाने के दूसरे तरीके आजमाए जाते हैं। कहीं जाति, धर्म के समीकरण बिठाए जाते हैं, तो कहीं पैसे को पानी की तरह बहाया जाता है। बाकी कसर पूरी करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाने की कोशिशें होती हैं। नेताओं की जो सभाएं कभी ओजस्वी भाषणों और दिलचस्प जुमलों के लिए याद की जाती थीं, उनमें अब गाली-गलौज का माहौल बनने लगा है।

जीएसटी के नकारात्मक प्रभावों की चुनौती

भरत झुनझुनवाला

जीएसटी लागू करने के लिए भाजपा और कांग्रेस पार्टियां एकमत रही हैं। इस व्यवस्था को कैसे लागू किया जाये, इस पर विवाद है। जीएसटी का आम आदमी के ऊपर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है। जीएसटी का सीधा प्रभाव यह होता है कि तमाम टैक्स की दरों को चुनिन्दा 3 या 4 टैक्स दरों में परिवर्तित कर दिया गया है। इससे व्यापार करना आसान हो गया है। सभी राज्यों में एक दर से जीएसटी लगने से राज्यों के बीच व्यापार सुलभ हो गया है। विचार यह था कि जीएसटी से व्यापार करना आसान हो जायेगा, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार उत्पन्न होंगे। यह जीएसटी का अप्रत्यक्ष सुप्रभाव हुआ। दूसरी तरफ जीएसटी का आम आदमी पर सीधे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब तक हम टैक्स पॉलिसी को जन कल्याण के एक अस्त्र के रूप में देखते थे। आम आदमी द्वारा खपत की गयी वस्तुएं जैसे साइकिल एवं सस्ते जूतों पर टैक्स की दर कम लगाई जाती थी और अमीर द्वारा खपत की जा रही वस्तुओं जैसे एयर कंडीशनर और मर्सिडीज कार पर टैक्स की दर अधिक लगायी जाती थी। जीएसटी के अंतर्गत इन दरों को एकल दिशा में ले जाया जा रहा है। वर्तमान में 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत की तीन दरें हैं लेकिन सरकार की मंशा है कि इन्हें भी एक ही दर पर ले जाये। साइकिल पर यदि पूर्व में 5 प्रतिशत टैक्स था तो वह अब 18 प्रतिशत हो जायेगा और मर्सिडीज कार पर यदि 28 प्रतिशत टैक्स था तो वह भी 18 प्रतिशत हो जायेगा। इस प्रकार आम आदमी द्वारा खपत किये जाने वाले माल पर टैक्स की दरें आमतौर पर बढ़ी हैं। इस कारण जीएसटी का आम आदमी पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। न्यूजीलैंड सरकार द्वारा किये गये एक अध्ययन में कहा गया है कि भिन्न दरों से गरीबों पर टैक्स का भार कम होता है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर जेम्स मिर्लीस द्वारा किए गये एक अध्ययन में कहा गया है कि एकल दर से गरीब पर टैक्स का भार बढ़ता है। आस्ट्रेलिया के शेरिदन कॉलेज द्वारा बोस्तवाना के लिए किये गये एक अध्ययन में भी इस बात की पुष्टि की गई है। जीएसटी का एक और तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राज्यों के बीच व्यापार करना आसान हो गया है। बड़ी कम्पनियों द्वारा इसका विशेषकर लाभ उठाया जा रहा है। इस कारण छोटे उद्योगों की परेशानी बढ़ी है। पहले राज्यों की सरहद के कारण उन्हें दूर स्थापित बड़ी कम्पनियों से एक प्राकृतिक संरक्षण मिलता था जो अब समाप्त हो गया है। इस कारण जीएसटी का छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। छोटे उद्योगों के मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2011-12 में हमारे देश की आय में छोटे उद्योगों का हिस्सा 29.6 प्रतिशत था जो कि 2016 में घट कर 28.8 प्रतिशत रह गया था। इन्हीं छोटे उद्योगों द्वारा अधिकतर रोजगार बनाये जाते हैं। छोटे उद्योगों के मंत्रालय के अनुसार छोटे उद्योगों द्वारा 11.2 करोड़ रोजगार बनाये गये हैं जबकि वित्त मंत्रालय के अनुसार बड़े निजी क्षेत्रों के उद्योगों में केवल 1.2 करोड़ रोजगार बनाये गये हैं। छोटे उद्योगों के दबाव में आने से कुल रोजगार का हनन हुआ है। जिससे आम आदमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जीएसटी के ये नकारात्मक प्रभाव पूरे विश्व में पाये गए हैं। आस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी द्वारा किये गये अध्ययन में पाया गया कि छोटे उद्योगों द्वारा अपनी कुल आय का तीन प्रतिशत हिस्सा जीएसटी के अनुपालन में खर्च किया जा रहा है। उद्योगों को सामान्यतः बिक्री का 15 प्रतिशत लाभ होता है। इसमें 3 प्रतिशत की गिरावट आई है। आस्ट्रेलिया के 6 में से 5 छोटे उद्योगों को जीएसटी से नुकसान हुआ है। न्यूजीलैंड की विलिंग्टन यूनिवर्सिटी ने पाया कि बड़े उद्यमियों की तुलना में छोटे उद्यमी जीएसटी अधिक अदा करते हैं। जीएसटी के अनुपालन के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है। छोटा उद्यमी एक लाख का कंप्यूटर खरीद कर साल में दस लाख का माल बेचता है। बड़ा उद्यमी उसी एक लाख का कंप्यूटर खरीदकर दस करोड़ का माल बेचता है। मलेशिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि मलेशिया के छोटे उद्यमों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बढ़ गया है। वे बंद होने की चिंता से जूझ रहे हैं। अब हम जीएसटी के आम आदमी पर समग्र विकास का आकलन कर सकते हैं। जीएसटी के अंतर्गत सभी माल पर समान दर से टैक्स वसूलने से आम आदमी पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ-साथ आम आदमी के लिए रोजगार बनाने वाले छोटे उद्योग दबाव में आते हैं, जिससे पुनः उसकी आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। साथ-साथ यह भी सही है कि जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था में कुशलता स्थापित होती है और विकास दर बढ़ती है। विकास दर के बढ़ने से रोजगार में वृद्धि होनी चाहिए। लेकिन यह कौतूहल का विषय है कि जीएसटी का यह सार्थक प्रभाव क्यों नहीं पड़ता दिख रहा है? जीएसटी के लागू होने से आम आदमी पर नकारात्मक प्रभाव मात्र क्यों पड़ रहा है। इस पहेली का उत्तर यह है कि जीएसटी के कारण आम आदमी पर टैक्स का बोझ बढ़ता है और छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने से उसके रोजगार का हनन होता है। इन कारणों से बाजार में मांग कम होती है। आम आदमी को साइकिल पर 5 प्रतिशत की जगह यदि 18 प्रतिशत टैक्स देना पड़े तो उसकी साइकिल खरीदने की क्षमता कम होती है। तदनुसार साइकिल बनाने वाली फैक्टरी का माल कठिनाई से बिकता है। इसलिए जीएसटी से बाजार में कुल मांग कम हो रही है। मांग के कम होने से निवेश कम हो रहा है। आर्थिक विकास के लिए मांग और निवेश का जो सुचक्र जरूरी है, वह सुचक्र टूट रहा है। पहले मांग उत्पन्न होती है और फिर उस मांग की पूर्ति के लिए निवेश होता है। मांग ही कम उत्पन्न होने से यह सुचक्र टूट रहा है, जिसके कारण हमारी विकास दर भी गिरी है और आम आदमी की कठिनाई भी बढ़ी है। जीएसटी के कारण अर्थव्यवस्था की कुशलता का लाभ नहीं मिल रहा है। जीएसटी लागू होने के कारण साइकिल की उत्पादन लागत कम हुई है लेकिन आम आदमी के पास साइकिल खरीदने के लिए क्रय शक्ति ही नहीं रही है।

यह ऐसे हुआ कि आम आदमी के सामने 56 भोग परोसकर उसके हाथ पीछे बांध दिए जाएं। इस प्रकार जीएसटी का कुल प्रभाव आम आदमी पर और अर्थव्यवस्था दोनों पर नकारात्मक हुआ है और मूल रूप से जीएसटी पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। चुनाव बाद सत्तारूढ़ पार्टी के लिए यह प्रमुख आर्थिक चुनौती होगी।

लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

ट्वीट

टिकट

आजम खान जैसों को टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। वह आदतन खासकर महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं। उनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, लेकिन क्या ठोस कार्रवाई होगी? उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। शर्मनाक है उनका व्यवहार!

रेणुका शहाणो, अभिनेत्री

ज्ञान गंगा

परोपकार

ओशो/ उनके प्रति कृतज्ञता की अनुभूति करो, जिन्होंने तुमसे कुछ ग्रहण किया है। वे लेने से इनकार भी कर सकते थे। उनका परोपकार तो देखो। उन्होंने तुम्हें अपने ऊपर बरसने दिया है, ठीक पानी से भरे बादल की तरह। जब कोई बादल पानी से लबालब भरकर बरसता है तो क्या तुम्हारे ख्याल से वह ढूंढ़ता फिरता है कि बारिश में भीगने लायक कौन है? क्या वह बादल ब्राह्मण के खेत में ज्यादा और गरीब शूद्र के खेत में कम पानी बरसता है? वह तो प्यासी धरती का कृतज्ञ भर होता है, जो उसे आनंद के साथ ग्रहण करती है। अचानक सूखी धरती नहीं रहती, वह रस और जीवन से परिपूर्ण हो उठती है। प्यासी धरती एक परोपकार ही तो करती है एक बादल का बोझ हल्का करके। वह बादल को मुक्त कर देती है ताकि बहती हुई हवा के साथ आसानी के साथ किसी भी दिशा में उड़ सके। लेकिन किसी धर्म ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। धर्मों की चिंता तो धन और सत्ता के साथ जुड़ी रही है, जो उन्हें अमीर लोगों से ही मिल सकते हैं। वे धनी लोगों को दान करने के बारे में समझाने की भरसक कोशिश करते रहे हैं..पर घुमा-फिरा कर। एक बौद्ध शास्त्र में परोपकार की चर्चा पढ़ते हुए मुझे अचरज हुआ कि धार्मिक समझे जाने वाले लोगों के दिमाग में कितनी चालाकी भरी होती है। मुझे नहीं लगता कि ये बातें स्वयं गौतम बुद्ध ने कही होंगी क्योंकि इनका संग्रह तो उनकी मृत्यु के बाद हुआ है। यह शास्त्र सबसे पहले परोपकार के सौंदर्य की चर्चा करता है, उसकी अच्छाई की चर्चा करता है, उस पुरस्कार की चर्चा करता है, जो परोपकारी को दूसरी दुनिया में मिलता है। अंत में कहता है कि लेकिन देना है तो केवल उनको दो जो उसकी पात्रता रखते हैं। फिर वह पात्र व्यक्ति को परिभाषित करता है। वह परिभाषा ऐसी है कि केवल एक बौद्ध भिक्षु ही उसमें फिट हो सकता है। हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों का भी यही रवैया है। कोई स्वीकार करने के परोपकार के बारे में नहीं सोचता क्योंकि उन्हें स्वयं अपने बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे तो धन के बारे में चिंतित हैं कि उसे कैसे प्राप्त किया जाए, लोगों को कैसे यकीन दिलाया जाए कि जो कुछ दे रहे हैं, उसमें बेहतर धंधा है। क्योंकि वे जो देंगे, उसमें भी ज्यादा उन्हें दूसरी दुनिया में पाने का आश्वासन होगा। यह कैसा परोपकार हुआ? परोपकार शतरे पर नहीं होता। वह तो सहज रूप से देने का नाम है और उस कृतज्ञता का नाम है कि उस अस्वीकार नहीं किया गया और उसे ग्रहण किया गया।

उपचुनाव के खर्च की जवाबदेही का विकल्प

अनूप भटनागर

लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सुधारों के हिमायती वर्गों में प्रत्याशियों के एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। इसकी प्रमुख वजह यह है कि यदि प्रत्याशी दोनों सीटों से चुनाव जीत गया तो उसे एक स्थान से इस्तीफा देना पड़ता है और निर्वाचन आयोग को इस तरह से रिक्त हुई सीट के लिये उपचुनाव कराना पड़ता है जो काफी खर्चीला होता है। इस तरह के अनावश्यक खर्च पर अंकुश लगाने के लिये ही निर्वाचन आयोग ने 2004 में एक प्रस्ताव दिया था जो अभी भी ठंडे बस्ते में ही है। यह संयोग ही है कि एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बीच ही कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा की दो सीटों अमेठी और वायनाड के लिये नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी 16वीं लोकसभा के चुनाव में दो स्थानों वाराणसी और वडोदरा से नामांकन पत्र दाखिल किया था और बाद में उन्होंने वडोदरा सीट से इस्तीफा दे दिया था। भारत में भी 1996 तक पाकिस्तान की तरह ही उम्मीदवारों के कई सीटों पर किस्मत आजमाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। पाकिस्तान में तो पिछले साल हुए चुनावों में प्रधानमंत्री इमरान खान ने चार सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि 1957 में भारत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ के टिकट पर तीन सीटों पर चुनाव लड़ा था। मुख्य निर्वाचन आयुक्त टी. एन. शेषन के कार्यकाल के दौरान चुनाव सुधारों ने गति पकड़ी और 1996 में जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके धारा 33.7 जोड़ी गयी। इस प्रावधान के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अधिकतम दो सीटों के लिये ही नामांकन दाखिल कर सकता है। हालांकि निर्वाचन आयोग चाहता था कि इसे एक सीट तक सीमित किया जाये ताकि दो स्थानों से एक ही प्रत्याशी के विजयी होने की स्थिति में उपचुनाव पर होने वाले खर्च से बचा जा सके। एक से अधिक सीटों के लिये नामांकन दाखिल करने वाले दिग्गज नेताओं में इन्दिरा गांधी और सोनिया गांधी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव तक शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में 2004 में एक प्रस्ताव सरकार को दिया था। आयोग करीब 15 साल पहले इस संबंध में दिये गये अपने प्रस्ताव पर आज भी कायम है लेकिन केन्द्र सरकार इस प्रस्ताव से इत्तेफाक नहीं रखती। यह मामला इस समय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है। देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिये हुए चुनाव सुधारों ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों की शक्ल बदल दी है। इसके बावजूद चुनाव में कई प्रत्याशी आज भी दो-दो सीटों से अपनी किस्मत आजमाते हैं। दो सीटों पर चुनाव लड़ने और दोनों पर ही विजयी होने के बाद निर्वाचित प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 70 के तहत दस दिन के भीतर किसी एक सीट से इस्तीफा देना पड़ता है। उपचुनावों पर अधिक खर्च आता है। प्रत्याशियों को एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने के लिये इस समय भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की एक जनहित याचिका न्यायालय के विचाराधीन है। इस संबंध में उन्होंने देश के संविधान के कामकाज की समीक्षा करने वाले आयोग के सुझाव का सहारा लिया है। न्यायालय ने इस याचिका पर निर्वाचन आयोग से उसका दृष्टिकोण जानना चाहा था। आयोग ने अपने जवाब में 2004 में दिये गये प्रस्ताव को ही दोहराया। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जनप्रतिनिधित्व कानून में उचित संशोधन किया जाये ताकि कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक स्थानों से चुनाव नहीं लड़ सके। आयोग का मत है कि दो सीटों से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिये सरकार के पास एक निश्चित राशि जमा कराना अनिवार्य किया जाये ताकि दो सीटों से विजय मिलने की वजह से रिक्त होने वाले एक सीट के उपचुनाव में इस राशि का उपयोग हो सके। आयोग का उद्देश्य इस तरह से प्रत्याशियों को दो सीटों से चुनाव लड़ने के प्रति हतोत्साहित करना और उपचुनाव पर होने वाले खर्च को नियंत्रित करना है। निर्वाचन आयोग भले ही इस बदलाव के पक्ष में हो लेकिन राजनीतिक दल और उसके नेताओं में इस तरह के संशोधन पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। यही वजह है कि एक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने संबंधी निर्वाचन आयोग का प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा है। इस तरह के बदलाव के प्रति सरकार की अनिच्छा के बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव सुधारों के मामले में हमेशा की तरह एक बार फिर न्यायिक हस्तक्षेप से ही यह बाधा भी दूर हो जायेगी।

आज का राशिफल

मेष **अर्थिक** पक्ष मजबूत होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। पारिवारिक उत्सव में हिस्सेदारी लेंगे। खान-पान में संयम रखें। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

वृषभ पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। नेत्र विकार की संभावना है। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।

मिथुन जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। व्यावसायिक योजना सफल होगी। अपने सामान की सुरक्षा के प्रति सचेत रहें। वाणी की सौम्यता आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

कर्क व्यावसायिक क्षेत्र में व्यवधान आ सकते हैं। भारी व्यय की संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। संतान के कारण चिंतित रहेंगे।

सिंह आर्थिक दिशा में किए गए प्रयास सफल होंगे। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

कन्या जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। वाणी की सौम्यता आपको धन लाभ करायेगी। आर्थिक उन्नति के योग हैं। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

तुला व्यावसायिक क्षेत्र में व्यवधान आ सकते हैं। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ सकता है। किसी रिश्तेदार के आगमन से मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। नए अनुबंध मिलेंगे। नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा।

धनु व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें।

मकर पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें। आपके पराक्रम तथा प्रभाव में वृद्धि होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

कुम्भ शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।

मीन राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। संतान के कारण चिंतित रहेंगे। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

गैर-प्रमुख संपत्ति बेचने के लिए केंद्रीय लोक उपक्रमों को मिलेगा 12 महीने का समय

नई दिल्ली (एजेंसी) ।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के पास वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित अपनी गैर-महत्वपूर्ण संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने के लिए 12 महीने का समय होगा। ऐसा नहीं होने पर वित्त मंत्रालय केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के बजटीय आवंटन को प्रतिबंधित कर सकती है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने सोमवार को सीपीएसई की गैर-महत्वपूर्ण संपत्ति तथा अचल शत्रु संपत्ति को बाजार पर चढाने या उसे बेचने को लेकर दिशानिर्देश जारी किया। मंत्रिमंडल के फरवरी में किए गए निर्णय के बाद यह कदम उठाया गया। दिशानिर्देश के अनुसार, दीपम सचिव की अध्यक्षता वाला एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) स्वयं से तथा नीति आयोग की सिफारिशों के आधार पर सीपीएसई की गैर-महत्वपूर्ण संपत्ति को चिन्हित करेगा। हालांकि इस बारे में मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति अंतिम निर्णय करेगी। एक बार मंत्री स्तरीय समिति द्वारा बाजार पर चढ़ाने को लेकर संपत्ति की पहचान कर ली जाती है, तो संबंधित कंपनियों को मंजूरी की तारीख से 12 महीने के भीतर इस कार्य को पूरा करना होगा। लोक उपक्रम विभाग (डीपीई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के तहत सीपीएसई को यह लक्ष्य दिया गया है जिसे उन्हें पूरा करना है। दिशानिर्देश में सीपीएसई को गैर-महत्वपूर्ण संपत्ति बेचने को लेकर अंतर-मंत्रालयी समूह से 12 महीने की समयसीमा से राहत प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। इसमें कहा गया है कि सीपीएसई के लिए किसी भी प्रकार के बजटीय समर्थन पर विचार व्यय विभाग और आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) तभी करेगा जब संपत्ति को बाजार पर चढ़ाने का लक्ष्य पूरा हो जाता है।

जेट एयरवेज की मुश्किलों के बीच स्पाइसजेट उठा रही फायदा, कंपनी के शेयरों में आया उछाल

बिजनेस डेस्क (एजेंसी)।

इंडिगो, जेट एयरवेज और एयर इंडिया ये तीनों विमानन कंपनियां वर्तमान में किसी न किसी तरह के संकट के गुजर रही हैं। ऐसे दौर में जब विमानन कंपनियों को भिन्न-भिन्न कारणों से अपने विमानों (बोइंग 737 मैक्स) को परिचालन से बाहर करना पड़ रहा है और अंतरर्राष्ट्रीय उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोकना पड़ रहा है तो इस बीच स्पाइसजेट फायदा उठाती नजर आ रही है। जेट एयरवेज ने अपनी अतरर्राष्ट्रीय उड़ानों को अस्थायी तौर पर रोक दिया है। वहीं, स्पाइसजेट ने मुंबई से कई अंतरर्राष्ट्रीय उड़ानों की घोषणा की है। जेट एयरवेज की अंतरर्राष्ट्रीय उड़ानें 18 अप्रैल तक निलंबित रहेंगी। वहीं आज जेट संकट पर उसका बोर्ड अहम बैठक करने वाला है। बजट कैरियर स्पाइसजेट ने सोमवार को घोषणा की थी कि वो मई अंत तक अपनी नॉन-स्टॉप फ्लाइट्स से कई अंतरर्राष्ट्रीय गंतव्यों को जोड़ेगी। एयरलाइन के मुताबिक वह अपनी फ्लाइट्स को मुंबई से हॉन्ग-कॉन्ग, जेद्दाह, दुबई, कोलंबो, ढाका, रियाद, बैंकॉक और काठमांडू से जोड़ेगी। स्पाइसजेट ने हाल ही में अपनी नॉन स्टॉप फ्लाइट्स से मुंबई से दुबई को जोड़ा था। साथ ही रोजाना डायरेक्ट फ्लाइट्स से बैंकॉक से जोड़ा था। एयरलाइंस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वो मुंबई से दुबई के बीच अपने परिचालन को और बेहतर करना चाहती है। स्पाइसजेट भारत की पहली और इकलौती विमानन कंपनी होगी जो कि जो कि अपनी डेली डायरेक्ट फ्लाइट्स को मुंबई से कोलंबो, मुंबई से ढाका, मुंबई से रियाद, मुंबई से हॉनकॉन्ग और मुंबई से काठमांडू तक जोड़ेगी। बजट कैरियर स्पाइसजेट ने मंगलवार को जानकारी दी कि उसने अपने बेड़े में पांच और 90 सीटर बॉम्बार्डियर क्त400 को जोड़कर क्षेत्रीय जेट बेड़े को 32 विमानों तक विस्तारित करने की योजना बनाई है। कंपनी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य घरेलू बाजारों में विशेष रूप से क्षेत्रीय मार्गों पर क्षमता को बढ़ाना है। मंगलवार के कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर स्पाइटजेट के शेयर 6.70 फीसदी की तेजी के साथ 127.35 रुपए प्रति शेयर के स्तर पर कारोबार करते नजर आए।

बेंगलुरू हवाईअड्डा से सफर करना हुआ महंगा,120 प्रतीशत बढ़ा शुलक

बेंगलुरू (एजेंसी)।

देश के तीसरे सबसे बड़े व्यस्त बेंगलुरु हवाईअड्डे को विस्तार परियोजनाओं के लिए शुलक बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसके कारण यात्रियों के लिये बेंगलुरू हवाईअड्डे से विमान यात्रा करना महंगा होने वाला है। हवाईअड्डा के आर्थिक नियामक प्राधिकरण (एईआरए) ने यात्रियों से टिकट के साथ वसूले जाने वाले उपयोगकर्ता विकास शुल्क में 120 प्रतीशत की भारी वृद्धि किए जाने को मंजूरी दी है। एईआरए का कहना है कि नई दरें चार महीनों के लिए लागू की गई हैं। बेंगलुरू हवाईअड्डा ने एक बयान में कहा है कि एईआरए के आदेश के साथ घरेलू उड़ान के लिये उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) को 139 रुपए से बढ़ाकर 306 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के मामले में 508 रुपए से शुलक बढ़ कर 1,226 रुपए हो गया है। नई दरें मंगलवार को शुरु होने वाली दरों में कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिये नये शुल्क में क्रमशः 120 प्रतीशत और 119 प्रतीशत की बढ़ोतरी की गयी है। संशोधित शुल्क 16 अप्रैल से 15 अगस्त के बीच खरीदे गये टिकट पर लागू होगा।

हवाईअड्डा निर्दशक का कहना है कि कुल 13,000 करोड़ रुपए की विस्तार योजना के दूसरे चरण में नए टिंमनल का निर्माण, दूसरा रनवे, सड़क तक पहुंचाने और मल्टी-मॉडल ट्रांसपोर्ट केंद्र का निर्माण के निर्माण के लिए शुलक लगाया जा रहा है।

दो करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियां बना सकती हैं जीएसटी आडिट रिपोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)।

जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ने अपने पोर्टल पर आडिट रिपोर्ट के लिये प्रारूप उपलब्ध करा दिया है। जिसमें दो करोड़ रुपये से अधिक सालाना कारोबार वाली कंपनियां वित्त वर्ष 2017-18 के लिये अब जीएसटी आडिट रिपोर्ट भरना शुरू कर सकती हैं। वित्त वर्ष 2017-18 वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का क्रियान्वयन का पहला साल है। इसके लिये आडिट रिपोर्ट 30 जून तक भरी जानी है। मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2018 को सालाना रिटर्न फार्म जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए और जीएसटीआर-9सी अधिसूचित किया था। जीएसटी परिषद ने दिसंबर में इन फार्म को भरने की अंतिम तारीख तीन महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। जीएसटीएन जीएसटीआर-9सी ऑनलाइन और आफलाइन भी उपलब्ध करवाया गया है। जिसे करदाता भर कर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। जीएसटीआर-9 जीएसटी के तहत पंजीकृत सभी करदाताओं के लिये सालाना रिटर्न फार्म है। जीएसटीआर-9ए एक मुश्त कर योजना अपनाने वाले करदाताओं के लिये है। जीएसटी-9सी एक मिलान ब्योरा है। जिसका सत्यापन चार्टर्ड एकाउंटेंट और कास्ट एकाउंटेंट करते हैं। वैसे तो करदाताओं को सालाना रिटर्न के साथ जीएसटीआर जमा करना होता है। जिनका कारोबार वित्त वर्ष में 2 करोड़ रुपये से अधिक रहा है। लेकिन ईवाई के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा है कि उद्योग लंबे समय से आफलाइन सुविधा तथा जीएसटीआर-9सी आनलाइन भरने की प्रक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा था।

संक्षिप्त समाचार

जेवराती मांग आने से बढ़ी सोने की चमक

नई दिल्ली । वैश्विक स्तर पर दोनों कीमती धातुओं में रही नरमी के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में जेवराती मांग आने से मंगलवार को सोना 150 रुपए चमककर 32,770 रुपए प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। चांदी भी 250 रुपए की मजबूती के साथ 38,350 रुपए प्रति किलोग्राम बिकी। विदेशों में सोने पर दबाव रहा। सोना हाजिर 3.50 डॉलर लुढ़ककर 1,284.60 डॉलर प्रति औंस रह गया। सोमवार को एक समय यह करीब दो सप्ताह के निचले स्तर 1,281.96 डॉलर प्रति औंस तक लुढ़क गया था। जून का अमेरिकी सोना वायदा भी 3.60 डॉलर फिसलकर 1,287.70 डॉलर प्रति औंस बोला गया। बाजार विश्लेषकों ने बताया कि वैश्विक स्तर पर मजबूत आर्थिक आंकड़े आने और अमेरिका तथा चीन के बीच व्यापार युद्ध के मुद्दे पर बनती सुलह से निवेशकों में शेयर बाजार के प्रति विश्वास लौटा है और वे सोने में निवेश के बदले शेयरों में जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं। इससे पीली धातु दबाव में आ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी हाजिर आज 0.04 डॉलर लुढ़ककर 14.94 डॉलर प्रति औंस रह गई। सोमवार को यह साढ़े तीन महीने से ज्यादा के निचले स्तर 14.81 डॉलर प्रति औंस तक लुढ़क गई थी।

जल्द ही भारत में भी आईफोन का होगा उत्पादन, मेक इन इंडिया से जुड़ेगा एप्पल

नई दिल्ली। भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान के तहत अब जल्द ही भारत में भी आईफोन तैयार होंगे। आईफोन की असैम्बलिंग करने वाली कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नॉलजी ग्रुप ने इस बात के संकेत दिए हैं। फॉक्सकॉन के चेयरमैन टेरी गोउ ने कहा है कि इस साल से भारत में आईफोन का बड़े पैमाने पर प्रॉडक्शन होने लगेगा। अब तक ज्यादातर चीन में ही प्रॉडक्शन करने वाली कंपनी की पॉलिसी में यह एक तरह से बड़ा बदलाव है। गोउ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत में आमंत्रित किया है। वह भारत में अपने विस्तार की योजना बना रहे हैं। बीते कई सालों से बेंगलुरु के एक प्लांट में एप्पल के पुराने फोन तैयार किए जा रहे हैं लेकिन लेटेस्ट मॉडल्स के लिहाज से यह पहला मौका होगा। ब्लूमबर्ग न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक फॉक्सकॉन की ओर से जल्दी ही भारत में नए आईफोन्स के प्रॉडक्शन का ट्रायल शुरू हो सकता है। कंपनी चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित अपनी फैक्टरी से यह उत्पादन शुरू करेगी। भारत दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ कर रहा स्मार्टफोन मार्केट है, जबकि चीन में एप्पल को स्थानीय कंपनियों हुवावे और शाओमी से कड़ी टक्कर झेलनी पड़ रही है। भारत में अधिक कीमत के चलते एप्पल का शेयर काफी कम है लेकिन यदि स्थानीय स्तर पर आईफोन का प्रॉडक्शन होता है तो कीमतें कम होंगी और इससे कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ सकता है।

मार्च में वनस्पति तेल का आयात 26 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। भारत के वनस्पति तेल का आयात मार्च के दौरान 26 प्रतिशत बढ़कर 14.46 लाख टन हो गया। इसकी वजह रिफाइंड पामतेल का आयात बढ़ना है। रिफाइंड पामतेल के बढ़ते आयात पर चिंता व्यक्त करते हुए, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने मांग की है कि किसानों और साथ ही खाद्य तेल प्रसंस्करणकर्ताओं की संरक्षा के लिए कच्चे और रिफाइंड तेल के बीच शुल्क अंतर को बढ़ाया जाना चाहिए। एसईए ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2019 में खाद्य तेल का आयात बढ़कर 13,93,255 टन हो गया, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11,22,685 टन था। अखाद्य तेलों का आयात दोगुना होकर 53,302 टन हो गया जो पहले 23,366 टन था। एसईए ने कहा, एक जनवरी, 2019 से वित्त मंत्रालय ने पाम तेल पर आयात शुल्क कम कर दिया और इसके अलावा मलेशिया से आयात होने वाले कच्चे पामतेल और पामोलीन के बीच शुल्क अंतर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया था।' उसने कहा, जैसा कि अनुमान था, आशंकाएं सच साबित होने लगी हैं और भारत में मलेशिया से आरबीडी पामोलिन का आयात बढ़ गया है। मलेशिया से लिए गये सीपीओ (कच्चे पाम तेल) और पामोलीन के बीच शुल्क अंतर कम किए जाने से आरबीडी पामोलिन का आयात बढ़ रहा है जो दिसंबर 2018 के 1,30,000 टन के आयात से बढ़कर मार्च 2019 में 3,00,000 टन से अधिक हो गया।' इस घटनाक्रम से भारत में पामतेल परिशोधन उद्योगों के लिए खतरे की घंटी होने की संभावना है। एसोसिएशन ने कहा कि इस घटनाक्रम के कारण सरसों दाना की कीमत गंभीर रूप से प्रभावित हुई है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी नीचे चल रहा है इससे सरसों किसानों की आय प्रभावित होगी। इस स्थिति को संभालने के लिए एक जनवरी, 2019 से पहले प्रचलित सीपीओ और आरबीडी पामोलिन के बीच 10 प्रतिशत के शुल्क अंतर को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है।

देश का सेवा निर्यात फरवरी में 5.5 प्रतिशत बढ़ा

मुंबई । देश का सेवा निर्यात 2018-19 के फरवरी महीने में 5.5 प्रतिशत बढ़कर 16.58 अरब डॉलर पर पहुंच गया। एक साल पहले इसी महीने में यह 15.71 अरब डॉलर था। रिजर्व बैंक के सोमवार को जारी आंकड़े के अनुसार, फरवरी 2019 का निर्यात जनवरी के 17.75 अरब डॉलर से कम है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार, इस साल फरवरी में सेवा आयात 3.3 प्रतिशत घटकर 9.81 अरब डॉलर रहा। एक साल पहले, इसी महीने में यह 10.14 अरब डालर था। इस साल जनवरी में आयात 11.3 अरब डॉलर था। केंद्रीय बैंक करीब 45 दिन के अंतराल पर देश के अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मासिक आंकड़ा जारी करता है। सेवाओं का मासिक आंकड़ा अस्थायी होती है और तिमाही आधार पर भुगतान संतुलन का आंकड़ा जारी होने के बाद इसमें संशोधन होता है।

पेट्रोल 5 पैसे सस्ता, डीजल हुआ महंगा

बिजनेस डेस्क (एजेंसी)।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल लगातार दो दिन की बढ़त के बाद मंगलवार को पांच पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया जबकि डीजल के दाम पांच पैसे प्रति लीटर बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल का दाम सोमवार के 72.98 के मुकाबले 72.93 रुपए प्रति लीटर रह गया वहीं डीजल की कीमत 66.26 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर पांच पैसे बढ़कर 66.31 रुपए प्रति लीटर हो गयी। देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को पेट्रोल के दाम पांच पैसे प्रति लीटर घट गये। वहीं डीजल की कीमत में पांच पैसे की वृद्धि दर्ज की गयी। दिल्ली के साथ ही मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी पेट्रोल पांच-पांच पैसे सस्ता हुआ तथा क्रमशः 78.50 रुपए, 74.95 रुपए और 75.69 रुपए प्रति लीटर पर आ गया। डीजल की कीमत दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई में पांच-पांच पैसे बढ़ायी गयी। इन जगहों पर यह क्रमशः 66.31 रुपए, 68.05 रुपए और 70.01 रुपए प्रति लीटर के भाव बिका। मुंबई में डीजल की कीमत 69.40 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गयी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नोएडा और गुड़गांव में में पेट्रोल की कीमत क्रमशः 72.79 रुपए और 72.25 प्रति लीटर तथा डीजल के दाम 65.51 रुपए और 65.40 रुपए प्रति लीटर हो गये। गौरतलब है कि तेल विपणन कंपनियां दोनों जीवाश्म ईंधनों की कीमतों की रोजना समीक्षा करती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्यों और डॉलर के मुकाबले रुपए के विनिमय दर को ध्यान में रखते हुये नयी कीमत तय की जाती है जो हर दिन सुबह छह बजे बदलती है।

डाक विभाग को 15 हजार करोड़ का घाटा, बीएसएनएल और एयर इंडिया को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम इंडिया पोस्ट ने घाटे के मामले में अन्य सरकारी उपक्रमों बीएसएनएल और एयर इंडिया को भी पीछे छोड़ दिया है। वित्त वर्ष 2019 में इंडिया पोस्ट के रेवेन्यू और खर्च के बीच का अंतर 15,000 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रमों बीएसएनएल और एयर इंडिया ने वित्त वर्ष 18 में क्रमशः 8,000 करोड़ रुपए और 5,340 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया था। दूसरे सरकारी उपक्रमों की तरह इंडिया पोस्ट ऊंची ऑपरेटिंग कॉस्ट और कर्मचारियों को कम्पन्सेशन जैसी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। कई पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के कारण कर्मचारियों की सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पोस्टल सर्विसेस से रेवेन्यू गिरता जा रहा है। वित्त वर्ष 19 में अलाउंस और वेतन की कॉस्ट लगभग 16,620 करोड़ रुपए रही, जबकि रेवेन्यू 18,000 करोड़ रुपए अर्जित हुआ। पीएसयू को अनुमान है कि वित्त वर्ष 20 में सैलरी और पेंशन पर खर्च क्रमशः 17,451 करोड़ रुपए और 10,271 करोड़ रुपए रहेगा, जबकि रेवेन्यू 19,203 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है।

वित्तीय संकट से बाहर निकलने की हो रही कोशिश

कंपनी वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए लगातार कोशिश कर रही है लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट और पारंपरिक मेलिंग सर्विसेस में उपलब्ध सस्ते विकल्पों के बीच असमानता के कारण इसमें नाकाम हो रही है। सूत्रों ने कहा कि इंडिया पोस्ट से अपनी 4.33 लाख इम्प्लाइज की वर्कफोर्स और 1.56 लाख पोस्ट ऑफिसेस के नेटवर्क के दम पर ई-कॉमर्स और अन्य वैल्यू एडेड सर्विसेस में संभावनाएं खंगालने के लिए कहा जा सकता है।

यूनिवर्सल सर्विसेस के चलते हो रहा घाटा

एक अधिकारी ने कहा, 'पोस्टल सर्विस जैसी यूनिवर्सल सर्विसेस के चलते घाटा होगा, क्योंकि सभी कमर्शियल बैंकों की कुल बैंक शाखाओं की तुलना में पोस्ट ऑफिस की संख्या ज्यादा है।' इंडिया पोस्ट अपने हर पोस्ट कार्ड पर 12.15 रुपए खर्च करता है लेकिन उसे सिर्फ 50 पैसे यानी लागत का 4 फीसदी ही मिलता है। उसकी पार्सल सर्विस, बुक पोस्ट, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के साथ भी ऐसा ही होता है।

नरेश गोयल बोली लगाने की रेस से बाहर, अस्थाई रूप से बंद हो सकता है काम-काजः सूत्र

बिजनेस डेस्क। नकदी संकट का सामना कर रही जेट एयरवेज को लेकर एक बड़ी खबर आई है। नरेश गोयल ने जेट की बोली प्रक्रिया से अपना नाम वापस ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक गोयल ने अपना नाम खुद वापस ले लिया है। वहीं बोर्ड की बैठक में जेट एयरवेज के मैनेजमेंट ने साफ किया है कि अगर फंड नहीं मिला तो एविएशन कंपनी के लिए काम-काज जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। यह संकेत भी दिए कि कंपनी अस्थाई तौर पर अपना काम-काज बंद कर सकती है। वहीं, इस खबर के बाद से शेयर बाजार में कंपनी के स्टॉक में 15 फीसदी तक गिरावट दर्ज हुई। इस समय जेट के महज 6-7 विमान ही उड़ान भर रहे हैं। विमानों की लीज का किराया नहीं देने के चलते जेट के करीब-करीब सभी विमान ठप पड़े हैं। पायलट और कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। जिसके चलते उन्होंने हड़ताल की धमकी दी थी। फिलहाल सोमवार को उन्होंने हड़ताल को टाल दिया। नागर विमानन मंत्री सुरेश प्रभु ने विमाने विमान किरायों में बढ़ोत्तरी और उड़ानों के रद्द होने सहित संकटग्रस्त जेट एयरवेज से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा का निर्देश दिया है। प्रभु ने नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खारोला को यात्रियों के अधिकार एवं सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश भी दिया। प्रभु ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। भारी आर्थिक तंगी से जूझ रही जेट एयरवेज पायलट बॉडी नेशनल एविएटर्स गिल्ड ने सोमवार को से अपील की थी कि वह 1500 करोड़ रुपए का वह 1500 करोड़ रुपए का फंड जारी करे। पिछले महीने डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान के तहत एयरलाइन में 1500 करोड़ रुपए का फंड डालना प्रस्तावित था। वहीं, जेट के पायलट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एयरलाइंस की करीब 20,000 नौकरियां भी बचाने की गुहार लगाई है।

कृषि मंत्रालय की रिपोर्टः इस साल 23 लाख हेक्टेयर पर आम की खेती होने का अनुमान

नई दिल्ली (एजेंसी)।

आम खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर है। इस बार आम का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले अधिक रह सकता है। यह अनुमान केंद्रीय कृषि मंत्रालय की तरफ से लगाया गया है। कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक आम उत्पादन सीजन 2018-19 में भारत में आम का उत्पादन 2.235 करोड़ टन रहेगा जबकि पिछले साल 2.182 करोड़ टन आम का उत्पादन रहा। मंत्रालय के अनुमान में इस सीजन के लिए आम की खेती का कुल अनुमानित रकबा भी बढ़ा हुआ है। इस साल 23 लाख हेक्टेयर पर आम की खेती होने का अनुमान है जबकि पिछले साल 22.6 लाख हेक्टेयर पर आम की खेती की गई थी। सबसे बड़ी बात है कि इस साल आम के निर्यात में भी बढ़ोतरी का अनुमान है। इसलिए भारतीय बाजार में आम के उत्पादन में बढ़ोतरी के बावजूद आम की कीमत में कोई खास राहत नहीं मिलेगी। दक्षिण कोरिया एवं सर्बिया जैसे देश इस साल भारतीय आम के लिए अपने-अपने बाजार को खोल रहे हैं। जापान में आम निर्यात का रास्ता पहले ही साफ हो चुका है। जापान आम निर्यात के लिए भारतीय प्रसंस्करण संयंत्रों का परीक्षण पहले ही कर चुका है। वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक इस साल आम के निर्यात में बढ़ोतरी के लिए सरकार की तरफ से कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी दूतावासों में भारतीय आम का स्वाद चखने के लिए मुफ्त में आम की व्यवस्था की गई है।

वहीं कई देशों के भारतीय दूतावास में यह इंतजाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस प्रयास की बदौलत इस साल आम के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 10-15 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 2017-18 में आम का निर्यात 5.9 करोड़ डॉलर का रहा जबकि 2016-17 में 6.7 करोड़ डॉलर आम का निर्यात किया गया था। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल आम निर्यात में गिरावट के कारण सरकार ने पश्चिम एशिया, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

गोपी तलाब गेट के पास युवक पर हमला

सूरत। मगंलवार को सूरत शहर के सलाबतपुरा पुलिस स्टेशन विस्तार में गोपी तलाब मेन गोट के पास ता. 15-4-2019 के रात लगभग 11 बजे युवक पर सलिया से हमला कर गंभीर रुप से घायल कर दिया।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार महेराजबीन इकबाल खान आलम खान पठाण ने सलाबत पुलिस स्टेशन में ता. 16-4-2019 में 1.45 के आसपास पी.एस.ओ. में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उनका पुत्र रात 11.00 बजे ता. 15-4-2019 में गोपी तलाब मेन गेट के पास जा रहा था कि आरोपी जुबेर, अग्गो, मुस्तुफा, आशिफ जिनका नाम पता मालूम नहीं ने उनके पुत्र को गंदी गालिया देते हुए सलिया से बाये कान के भाग में तथा दाहिने पग पर हमला किया। उनकी मार से फरियादी के पुत्र को गहरी चोटे आयी है और जान से मारने की धमकी भी दी है। सलाबतपुरा पुलिस ने ता. 16-4-2019 में गु.र.नं. 157/2019 इ.पी.को. की कलम 324,323,504,506 (2) और 114 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। माले क जांच प्रो. पु. स. इं. सी.एफ. ठाकोर कर रहे है।

बीजेपी विधायक की मतदाताओं को धमकी- भाजपा को वोट नहीं दिया तो कोई काम नहीं मिलेगा

गांधीनगर। लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे गुजरात के एक और विधायक ने मतदाताओं को धमकी दी है। फतेहपुरा से विधायक रमेश कटारा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी साहब ने मतदान केंद्रों में कैमरे लगा रखे हैं, अगर आपने भाजपा के अलावा किसी और को वोट दिया तो उन्हें पता लग जाएगा और फिर आपको कोई काम नहीं मिलेगा। विधायक ने जनसभा में मौजूद लोगों से कहा, कमल का निशान और जसवंत सिंह भाभोर (भाजपा उम्मीदवार) की तस्वीर नजर आएगी, आपको वही बटन दबाना है। वहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोदी साहब ने इस बार कैमरे लगवा रखे हैं। कौन भाजपा को वोट देगा और कौन कांग्रेस को वोट देता है, सब पता लग जाएगा। इससे पहले गुजरात के जल आपूर्ति मंत्री कुंवरजी बावलिया का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें जब कुछ महिलाओं ने उनसे पीने के पाने की समस्या को लेकर शिकायत की तो उन्होंने जवाब में कहा कि क्या आप लोगों ने मुझे वोट दिया था।

पुलिस के छापे में उधना में खड़े टेंकर से लाखों रुपये की देशी व विदेशी शराब बरामद

सूरत। मंगलवार को सूरत शहर के उधना रोड़ नं. 6 के पास संजय नगर में स्टेट मानिटरिंग सेल गुजरात राज्य गांधीनगर द्वारा छापे के दौरान लाखों रुपये का देशी व विदेशी दारू की बरमादगी की है।

पुलिस सुत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार आज ता. 16-4-2019 को साय 5 बजे स्टेट मानिटरिंग सेल ने सूरत शहर के उधना रोड़ नं. 6 के संजय नगर विस्तार पावर सब स्टेशन के पास राज मोहम्मद उर्फ राजू प्लास्टि पुत्र चांद सैयद की मालिकी की चाल में तथा प्लास्टि के गोड़ाउन में छापा मारकर भारतीय बनावट की ऐपीसोड़ क्लासिक व्हिस्की की विदेशी दारू का बड़ा जत्था कुल 4267 नग बड़ी वोटल कीमत लगभग 17,06,800 अशोक लेलैंड टेंकर नं. जी.जे06 एटी 9093 अनुमाननत कीमत 12,00,000 मोबाइल फोन 2 नग कीमत लगभग 5500 टोल टेक्स रसीद उपर टेल कम्पनी के सिम कार्ड का खाली कवर, डुप्लीकेट आर.सी. बुक तथा अन्य कागजों के साथ कुल 29,12,300 का मुद्दामाल कब्जे में लेकर जब्त किया तथा मोहम्मद रियाज मोहम्मद रफीक शेख व राज मोहम्मद उर्फ राजू प्लास्टिक चांज सैयद को गिरफ्तार किया। उधना पु.स्टे.3 गु.र.नं. 326/2019 प्रोहिविशन एक्ट कलम 65(ए) (ई) 116(बी)81,83,86,98(2) तथा इ.पी.कोड की कलम 464,471 के तहत केस दर्ज किया तथा फरार आरोपियों सफीफुद्दीन उर्फ लाला तारिकुद्दीन फारुकी, सरीफ तारिकुद्दीन फारुकी को वान्टेड जाहेर किया। उपरोक्त सन्दर्भ में फरियादी स.त. आ.पुलिस के मुकेश भाई तलसी भाई ब.न. 82 स्टेट मानिटरिंग सेल में कार्यरत है।

हिम्मतनगर, सुरेन्द्रनगर और वल्लभ विद्यानगर में सभा

नरेन्द्र मोदी आज से दो दिन गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे

जनता का आशीर्वाद लेने के लिए और लाखों कार्यकर्ता के मेहनत से गुजरात की सभी सीट पर भाजपा की जीत

अहमदाबाद । भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी ने बताया कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी १७ अप्रैल को हिम्मतनगर, सुरेन्द्रनगर, आणंद और १८ अप्रैल को अमरेली में जनसभा करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में लेकर पूरे भारत में भगवा का माहौल है तब गुजरात की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए और लाखों कार्यकर्ताओं के मेहनत से गुजरात की सभी २६ सीट पर भाजपा की जीत हो इस उद्देश्य से दौरा करेंगे। गुजरात के लोकप्रिय नेता और विश्व में लोकप्रियता हासिल कर रहे मोदी देश में फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। १७ अप्रैल को तीन जनसभा करेंगे जिसमें से एक बजे हिम्मतनगर में जनसभा आयोजित किया जाएगा जबकि दोपहर में तीन बजे सुरेन्द्रनगर लोकसभा सीट के तहत पुलिस परेड ग्राउंड पर सभा आयोजित की जाएगी जबकि शाम को पांच बजे आणंद लोकसभा सीट के तहत वल्लभ विद्यानगर शास्त्री मैदान में जनसभा होगी। पहले दिन में तीन ज सनभा करने के बाद १८ अप्रैल को अमरेली में जनसभा आयोजित की जाएगी। भाजपा की अखबारी सूची में बताया गया है कि, मोदी के अलावा स्मृति इरानी भी बुधवार को चुनाव प्रचार करेगी जिसके तहत पाटण लोकसभा मत क्षेत्र में आते पाटण में पटेल ऑटो मोबाइल पीछे के मैदान में सुबह में १० बजे उनकी सभा होगी जबकि ३.३० बजे सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद ४.३० बजे जूनागढ़ में गार्डन चौक में सभा होगी। उनकी शाम को छह बजे गोंडल मांडवी चौक में सभा होगी। इसके अलावा रात को नौ बजे राजकोट में पाणीघोडा में एक बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज भी चुनाव प्रचार करने वाली है जिसके तहत १८ तारीख को दोपहर में दो बजे अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम लोकसभा मत क्षेत्र में अहमदाबाद शहर के सीटीएम कुशाभाई ठाकरे हॉल में उनकी सभा होगी। इसी दिन शाम को छह बजे जामनगर में टाउन हॉल में उनकी बैठक होगी।

लोकसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की कवायद शुरू हो चुकी है जिसके तहत सुरक्षा जवानों ने विभिन्न स्थलों पर पहुंच रहे है।

एडवांस टैक्स रिबेट योजना की अंतिम तारीख ५ मई

म्युनिसिपल तिजोरी में ७८ करोड़ से ज्यादा की आय

अहमदाबाद। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शासकों द्वारा पिछले २० वर्ष से संपत्ति टैक्स के करदाताओं को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में इस वर्ष के अलावा बाकी वर्षों का संपत्ति टैक्स भरपाई करने पर टैक्स ब्याज में १०० फीसदी तक की राहत दी जाती थी। हालांकि यह स्कीम को गत वर्ष पहली बार बंद की गई थी। इसके अलावा टैक्स सीलिंग अभियान में पूरा टैक्स चुकाने वाले नागरिक की ऑफिस या दुकान के सील खोले जाते थे। बीएसएनएल जैसी सरकारी ऑफिस को पहली बार सील किया गया था। यह सभी कारणों से इस वर्ष एडवांस संपत्ति टैक्स रिबेट योजना में म्युनिसिपल तिजोरी में ७८.४८ करोड़ रुपये आये है। एएमसी प्रशासन द्वारा संबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में पहले से संपत्ति टैक्स की भरपाई करने वाले करदाताओं को संपत्ति टैक्स के बिल में १० फीसदी की राहत दी जाती है। एडवांस संपत्ति टैक्स रिबेट योजना के तौर पर जानी जाती इस योजना को प्रशासन द्वारा चालू रखी गई है। गत ५ अप्रैल, २०१९ से इस योजना को लागू किए जाने से इसकी अंतिम तारीख आगामी ५ मई, २०१९ है। हालांकि करदाताओं में गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ की तुलना में इस वित्तीय वर्ष २०१९-२० में डबल से ज्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। गत वित्तीय वर्ष में प्रशासन ने डिफोल्टर्स के खिलाफ सख्ती अपनाते हुए करदाता एडवांस में संपत्ति टैक्स चुकाने के लिए उत्सुक रहे होने की चर्चा रही है। यह योजना के तहत प्रशासन को गत दिन तक में मध्य जोन में से ९.९० करोड़ रुपये, उत्तर जोन में ४.४८ करोड़ रुपये, दक्षिण जोन में ६.८० करोड़ रुपये, पूर्व जोन में ७.२९ करोड़ रुपये, पश्चिम जोन में २१.३९ करोड़ रुपये, और नये पश्चिम जोन में सबसे ज्यादा २८.५४ करोड़ रुपये की आय हुई है। गत वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के दौरान म्युनिसिपल तिजोरी को सिर्फ ३८.९४ करोड़ रुपये की आय हुई थी।

कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट के नाम पर झूठ फैला रही है

सुप्रीम के नाम पर राहुल जनता को गुमराह कर रहे

मोदी ईमानदार-परिश्रमी पीएम है, चौकीदार बनकर देश की तिजोरी पर कांग्रेस की बुरी नजर नहीं लगने देगा : रुपाणी

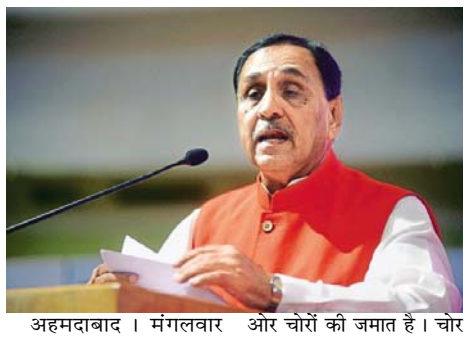

अहमदाबाद। मंगलवार को मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने जूनागढ़ लोकसभा सीट के उम्मीदवार राजेशभाई चुडासमा के समर्थन में उना में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि, इस बार का चुनाव भाजपा या कांग्रेस तक सीमित नहीं है, लेकिन देश किसके हाथ में सुरक्षित है इसके लिए है। मां भारती ज गत जननी बने इसके लिए है। एक ओर चौकीदार है, तो दूसरी ओर चोरों की जमात है। चोर चौकीदार को चोर कहता है। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा बारबार नरेन्द्र मोदी चोर है यह झूठ और बेबुनियाद निवेदन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, हम नरेन्द्र मोदी को कभी भी चोर नहीं कहा है।कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के नाम पर राहुल गांधी जनता को गुमराह कर रहे है। नरेन्द्र मोदी ईमानदार और परिश्रमी प्रधानमंत्री है। दिल्ली में चौकीदार बनकर देश की तिजोरी पर किसी का पंजा नहीं लगने देंगे। यह चोरों की जमात को ऐसे ईमानदार और परिश्रमी प्रधानमंत्री पसंद नहीं है, इसी वजह से अब बारबार मोदी हटाओ, मोदी हटाओ कह रहे है। झूठ बोलना, जोर से बोलना, बारबार बोलना यह कांग्रेस का स्वभाव है। कांग्रेस को हार का संकेत मिल गया है। पहले चुनाव में हार जाने के बाद ईवीएम के बहाने निकालते थे देश में लोकसभा की प्रथम चरण की चुनाव बाद वह अभी से कहने लगे है कि ईवीएम की वजह से बीजेपी जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, हम नरेन्द्र मोदी को कभी भी चोर नहीं कहा है।कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट के नाम पर गुमराह कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा है।

यह बताता है कि कांग्रेस हार रुपाणी ने आगे बताया कि, यूनाइटेड नेशन ने हमारे पीएम नरेन्द्र मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड उनके अद्भूत कार्य के बदले में दिया है। यह सिर्फ पीएम का सम्मान नहीं है, लेकिन देश की १३० करोड़ जनता का सम्मान है। पहले ग्लोबल वोर्निंग के लिए भारत को जिम्मेदार बताया जाता था। आज भारत को चैंपियन ऑफ द अर्थ का पुरस्कार दिया जाता है यह बताता है कि पीएम मोदी की कड़ी मेहनत द्वारा देशहित और विकास कार्यों को करके भारत देश को सम्मान दिलाया है।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100, E-mail: krantisamay@gmail.com (subject to surat jurisdiction)**